विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : मैं २१ मई, १९६२ को सभा को दी गई अंतिम प्रतिवेदन के बाद संसद की दोनों सभाओं द्वारा गत सत्र में पारित किये गये और राष्ट्रपति की अनमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२

(२) वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२

(३) भेषज (संशोधन) विधेयक, १९६२

(४) विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६२

(५) विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९६२

(६) राष्ट्रपति को पेंशन (संशोधन) विधेयक, १९६२

मैं २१ मई, १९६२ को सभा को दी गई अन्तिम प्रतिवेदन के बाद संसद् की दोनों सभाओं द्वारा गत रात्र में पारित किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६२ की एक प्रति राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में सभा पटल पर रखता हूं ।

लद्दाख की स्थिति के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय, मैं २८ नवम्बर, १९६१ को सभा पटल पर श्वेत पत्र सख्या ५ रखा था। उस श्वेत पत्र में भारत सरकार और चीन सरकार के बीच बाद में आये गये नोट्स (टिप्पण) ज्ञापन और पत्र सम्मिलित थे। अब मैं एक दूसरा श्वेत पत्र संख्या ६ सभा पटल पर रख रहा हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २५६/६२**]। इसमें १० नवम्बर, १९६१ के बाद चीन सरकार को भेजे गये हमारे लगभग ९० नोट्स और चीन सरकार द्वारा भेजे गये लगभग ७५ नोट्स सम्मिलित हैं। इनमें से कई समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हो चुके हैं। चीन सरकार कभी कभी हमको भेजे जाने वाले अपने पत्रों और नोट्स को हम तक पहुंचने से पहले भी प्रकाशित कर देती है। इसलिये हमने भी अपने उत्तरों को कुछ पहले प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। पहले हम ऐसा नहीं करते थे। राजनयिक प्रथा के अनुसार, सामान्यतया ऐसे पत्रों और नोट्स का प्रकाशन उनके मिलने के बाद ही किया जाता है। हमने इस राजनयिक प्रथा की ओर चीन सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और आशा है कि वह भविष्य में इस प्रथा का पालन करेगी। हमने इसी कारण चीन सरकार को भेजे गये २६ जुलाई, १९६२ को अपने अन्तिम नोट को प्रकाशित नहीं होने दिया है। मैं अब उसे सभा पटल पर रख रहा हूं। श्वेत पत्र संख्या ६ में यह सम्मिलित नहीं है ।

मैंने संसद् के पिछले सत्र में बताया था कि चीन को भारतीय राज्य क्षेत्र में और आगे न बढ़ने देने के लिये सरकार ने क्या-क्या उपाय किये हैं। हमारी सरकार के वे प्रयत्न जारी हैं और कई सैनिक चौकियां भी स्थापित की गई हैं। विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गई इन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अनेक सैनिक चौकियों के कारण, अब चीन सरकार की सेनाओं के लिये बिना किसी मुठभेड़ के और आगे बढ़ाना काफी मुश्किल हो गया है। चीन सरकार ने हमारे पास इतने सख्त और एक तरह से गाली गलोज से भरे जो नोट्स भेजे हैं, उनको हमें इस नयी परिस्थिति के साथ रखकर देखना चाहिये। हमें इसी दृष्टभूमि में उनकी व्याख्या करनी चाहिये। हमने अपने सब नोट्स में चीनी अधिकारियों से बार बार उन की आक्रमणात्मक कार्यवाइयों के खतरों का उल्लेख किया है और उन को बताया है कि अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमारा दृढ़ निश्चय है यद्यपि हम झगड़े को होने से रोकने का प्रयत्न करेंगे।

हाल के सप्ताहों में अधिक संख्या में चीनी सेनाएं कई बार हमारी चौकियों के बिल्कुल पास तक उन को परेशान और हैरान करने की दृष्टि से आए। ऐसा गाल्वान घाटी में हुआ है हमारे सैनिकों ने अत्यन्त संयम रखा और चीनी सेनाओं के द्वारा अत्याधिक उत्तेजित किये जाने के बावजूद भी आदर्श, उत्साह एवं धर्य का प्रदर्शन किया। तदुपरांत चीनी सेनाएं कुछ सीमा तक पीछे हट गई, किन्तु इस क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेनाएं बिल्कुल समीप हैं यद्यपि इस क्षेत्र में अभी तक कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई।

चिप चैप घाटी की निचली तराई में, एक भारतीय गश्ती दस्ते पर, जो अपना नियमित दैनिक कार्य कर रहा था, चीनी सैनिकों ने धावा कर दिया और राइफल, मशीन गन तथा मौर्टर आदि से गोली चलाई। हमारी सेनाओं को आत्मरक्षा में गोली का उत्तर गोली से देना पड़ा। इस घटना में भारतीय दस्ते के दो सैनिक घोयल हो गए, एक को थोड़ी सी चोट आई। दूसरी घटना पांगोई क्षेत्र में हुई। उत्तेजना के बावजूद हमारी सेनाओं ने वहां चीनी सैनिकों पर गोली नहीं चलाई।

इन घटनाओं के बारे में चीनी प्रचार की एक चाल यह आरोप लगाने की रही है कि भारतीय दस्तों ने चीनी सेनाओं को चारों ओर से घेर कर उन पर गोली चलाई है, जब कि चीनियों ने चिल्लाकर हमारे सैनिकों से आक्रमण न करने के लिये कहा है। हम ने देखा है कि ये आरोप निराधार हैं और हमारी चौकियों या गश्ती दस्तों के विरुद्ध चीनी लोगों की आक्रमणात्मक कार्यवाई को छिपाने का केवल प्रयत्न है। जैसा कि सभा को श्वेत पत्र में दिये गये पत्र व्यवहार से पता चलेगा, चीनी नोटों में दोतरफा रुख अपनाया गया है। नोट के पहले भाग में सामान्यतः निराधार आरोप लगाये गये हैं, अधिकतर बढ़ा चढ़ा कर तथा गाली गलौच की भाषा में, तथा उत्तर भाग में चीनी लोगों को यह इच्छा दर्शाई गई है कि वे शान्तिपूर्ण बातचीत के द्वारा हमारे सीमा संबंधी विवादों का निपटारा करना चाहते हैं।

लद्दाख क्षेत्र में अभी हाल में जो तनाव बढ़ा है उसका कारण यह है कि उस क्षेत्र में चीनी सैनिक हलचलों में वृद्धि हुई है, यह बात चीनियों की उस उदघोषणा के प्रतिकूल है जो कि उन्होने इस प्रश्न को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के संबंध में व्यक्त की थी। हम भारतीय स्वभाव एवं परम्परा से ही शांति प्रिय हैं। हम बातचीत और चर्चा द्वारा मतभेदों के निपटारे में विश्वास करते हैं। अतः चीनियों द्वारा इस अप्रत्याशित आक्रमण से हमें अत्यधिक आश्चर्य और दुख हुआ। चीन के इस आक्रमक रवैये और उनकी उद-घोषणा तथा व्यवहार में अंतर होने के बावजद भी हम चीन से अपने मतभेदों को पारस्परिक चर्चा व बातचीत के द्वारा निपटाना चाहते हैं, तथापि साथ ही हम अपनी क्षेत्रीय अखंडता

पर किसी प्रकार के अतिक्रमण का सामना दृढ़ता और आवश्यकता होने पर, बल प्रयोग द्वारा करने से भी नहीं हिचकेंगे।

चीन सरकार को १४ मई, १९६२ को भेजे गये एक नोट में, इस उद्देश्य से कि इस प्रश्न का शांतिपूर्वक बातचीत द्वारा हल हो सके, हमने यह ठोस सुझाव रखा था कि दोनों पक्ष लद्दाख क्षेत्र में उस सीमा पर हट जायें जिसका कि उन्होंने दावा किया है। चीन इस पर तैयार नहीं हुआ। इसके बावजूद पिछले कुछ महीनों में हुई वारदातों से तनाव में वृद्धि हुई है। हमने अभी हाल में २६ जुलाई, १९६२ को भेजे गये अपने एक नोट में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने तथा तनाव को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा उनसे भारत द्वारा रखे गये ठोस सुझावों को अमल में लाकर सीमा विवाद के शांतिपूर्ण हल के लिये आवश्यक वातावरण तैयार करने पर पुनः बल दिया। मैं भारत सरकार द्वारा २६ जुलाई को भेजे गये नोट से निम्नलिखित पैरा उद्धृत करता हूं :—

> "पैराग्राफ ८ वर्तमान तनाव कम होने और उचित वातावरण के बनने पर भारत सरकार, भारत–चीन सीमा के प्रश्न पर अधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर आगे चर्चा करने के लिये तैयार है, जैसा कि भारत के प्रधान मंत्री और चीन के प्रधान मंत्री श्री चाउ-एन-लाई की १९६० में हुई बैठक में तय हुआ था। भारत सरकार आशा करती है कि चीन सरकार वर्तमान तनावों को कम करने और बातचीत के लिये उचित वातावरण बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझावों के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करेगी।"

हमारे इस पत्र का उत्तर हमें कल शाम को प्राप्त हुआ। यह उत्तर बहुत ही निराशाजनक है क्योंकि चीन सरकार ने अपने आरोपों को दुहराया है और उसका रवैया अब भी वही है जो पहले था। उसने अपने अन्तिम पैराग्राफ में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये हैं :—

> "भारत–चीन सीमा के प्रश्न पर दोनों देशों के अधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर आगे चर्चा करने के बारे में भारत सरकार ने अपने पत्र में जो सुझाव दिये हैं उन्हें चीन सरकार स्वीकार करती है। ऐसी चर्चा के लिये पहले से ऐसी शर्तें रखना आवश्यक नहीं है। सच तो यह है कि यदि भारत सरकार चीन के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही बन्द कर दे तो सीमा की स्थिति को लेकर जो तनाव उत्पन्न हुए हैं वे एक दम कम हो जायेंगे। चूंकि, न तो चीन की सरकार और न भारत सरकार ही लड़ाई करना चाहती है और चूंकि दोनों सरकारें सीमा सम्बन्धी विवाद को बातचीत के जरिये शान्तिपूर्ण तरीके से हल करना चाहती हैं, इसलिये भारत–चीन सीमा के प्रश्न पर दोनों देशों के अधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर आगे की जाने वाली चर्चा अब और स्थगित न की जाये। चीन सरकार प्रस्ताव करती है कि इस प्रकार की चर्चा शीघ्रातिशीघ्र आयोजित की जाये और यह चर्चा किस स्तर पर हो, किस तारीख को हो, कहां हो और चर्चा सम्बन्धी प्रक्रिया की अन्य बातों को राजनयिक परामर्श द्वारा तुरन्त तय कर लिया जाये। चीन की सरकार आशा करती है कि भारत सरकार इस प्रस्ताव के पक्ष में निर्णय करेगी और इस पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करेगी।"

[श्री हरि विष्णु कामत]

हम चीन सरकार के इस नोट पर विचार कर रहे हैं और उसे जल्दी ही उत्तर दे देने की उम्मीद रखते हैं। हम संसद् को घटनाओं की जानकारी देते रहेंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या १९६० में दिखाये गये नक्शे के अनुसार चीनी लद्दाख की पश्चिमी सीमा में जहां तक बढ़े हैं, वहां तक बलपूर्वक कब्जा किया गया है।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मैं प्रधान मंत्री से यह बात पूछना चाहता हूं कि क्या चीनी विदेश मंत्री द्वारा स्विटजरलैंड में दिये गये वक्तव्य के उपरांत भी बातचीत का कोई आधार निकल सकता है। तथा क्या २४ तारीख के बाद से लद्दाख में कोई इस प्रकार की घटनायें नहीं हुई?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस विषय पर या तो प्रश्न ही पूछ सकते हैं या इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। माननीय सदस्यों को इन दो में से एक को चुनना है।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, यह सीमा का प्रश्न, लद्दाख का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देश के सम्मान का प्रश्न है, देश की सावरेनटी का सवाल है। आए दिन हम देखते हैं कि हमारी भूमि हम से छीनी जा रही है। सरकार देश की सीमाओं की रक्षा करने में असमर्थ रही है। हम इस पर बहस करना चाहेंगे, प्रश्न पूछना नहीं चाहेंगे। प्रश्न अनेकों बार पूछे जा चुके हैं, कुछ निकला नहीं है। सदन की यह इच्छा है कि इस पर बहस हो।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : हमें यथाशीघ्र इस विषय पर चर्चा करनी चाहिये जिससे कि प्रधान मंत्री को सदस्यों की भावनाओं का परिचय मिल सके।

श्री बागड़ी (हिसार) : मैं अर्ज करूंगा कि इससे बड़ा सवाल पार्लियामेंट के सामने कोई दूसरा आ नहीं सकता है। यह ठीक है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया है और इससे हमें कुछ जानकारी मिल गई है। लेकिन सवाल जानकारी का नहीं है। सवाल नीति का है। हम कौन सी नीति अपनायें कि इस देश को बचाया जा सके...

अध्यक्ष महोदय : आप बहस चाहते हैं।

श्री बागड़ी : बहस नहीं, मैं तो सजैशन दे रहा हूं। ऐसी क्या बात हो गई कि दो मिनट में बहस हो गई।

मैं अर्ज कर रहा था स्पीकर साहब, कि मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट का वक्त बड़ा कीमती है। लेकिन अगर हम वक्त दे सकते हैं, मक्खी, मच्छर टैक्सों के वास्ते, तो जो इस तरह के अहम मसले हैं.....

अध्यक्ष महोदय : आप कहें कि आप क्या चाहते हैं?

श्री बागड़ी : हिन्दुस्तान की जो नीति है उसी का यह नतीजा है कि काश्मीर के दो टुकड़े हो गए हैं और एक आजाद काश्मीर बन गया है। अगर यही नीति चलती रही

---

†मूल अंग्रेजी में

लो लद्दाख के भी दो टकड़े हो जाएंगे। इस वास्ते सवाल बहस का नहीं है। हम एड-जर्नमेंट मोशन चाहते हैं और चाहते हैं कि उसको एडमिट किया जाए। कौम को चेतावनी दी जानी चाहिये और पार्लियामेंट को अपने सुझाव देने चाहियें। ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक ने कह दिया "अहम् ब्रह्मास्मि" और दूसरे ने कह दिया "तथास्तु"।

†**श्री प्र० के० देव** : प्रधान मंत्री के वक्तव्य से मेरी इस बात की और भी पुष्टि होती है कि इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव ही समीचीन होगा, चाहे कुछ हो इस विषय पर तत्काल चर्चा की जाये।

†**श्री फ्रैंक एंथनी** (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : वस्तु स्थिति को देखते हुये इस विषय पर तत्काल सभा में चर्चा की जानी अनिवार्य है।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार प्रार्थना कर चुका हूं....

अध्यक्ष महोदय : आपकी बारी आयगी तो आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर एक मैम्बर साहब को मौका मिल ही जाय।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं प्रार्थना करूंगा कि इस विषय पर बहस होनी चाहिये और बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिय और वह भी हिन्दी में होनी चाहिये। यह हिन्दुस्तान है इंग्लिस्तान नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने स्थगन प्रस्ताव पढ़ लिया है और अब मैं उनको अपना दृष्टिकोण बतला रहा हूं। मैं उनको यह सलाह दूंगा कि यदि वे स्थगन प्रस्ताव के स्थान पर एक चर्चा की मांग करें, तो अधिक अच्छा होगा। इसीलिये मैंने माननीय सदस्यों से कहा है कि वे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो ४ बजे हो रही है, आकर भाग लें और चर्चा की मांग करें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं चर्चा के लिये बिलकुल तैयार हूं। मेरा इरादा यह था कि में आपसे विदेशी मामलों पर चर्चा के लिये एक दिन नियत करने की मांग करूं जिसके दौरान मैं यह मामला उठाया जा सकें। किन्तु एक बात जो मैं स्वीकार नहीं कर सकता यह है कि मैं अपनी चिट्ठियां जो अन्य सरकारों को भेजी जाती हैं, सदन की सलाह लेने के बाद भेजा करूं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मेरा सुझाव है कि चर्चा लद्दाख स्थिति तक ही सीमित रखी जाय और उसके लिये अलग समय रखा जाये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो कार्य मंत्रणा समिति में दिन और समय निश्चित किया जा सकता है।

वित्त मंत्री की हाल की पश्चिमी यूरोप की यात्रा के बारे में वक्तव्य

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं २ जुलाई को, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद् की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने और यूरोपीय आर्थिक

---

†मूल अंग्रेजी में